प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

# शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 13 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 21 – 28 मार्च 2022 मूल्य पांच रूपए

# प्रदेश में आप के पावं पसारते ही भिण्डरावाला के फोटो पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का अर्थ?

- भिण्डरावाला आतंकी या संत सरकार अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं
- वीरेश शांडिल्य ने गृह मंत्री से पूछा भिण्डरावाला का स्टेटस
- क्या यह विवाद राजनीतिक कारणों से उठाया जा रहा है

**शिमला/शैल।** आम आदमी पार्टी ने पंजाब पर कब्जा करने के बाद हिमाचल पर ध्यान केंद्रित करते हुए यहां चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का दावा दाग दिया है। इस दावे के साथ ही कांग्रेस और भाजपा के नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आप में जाना शुरू भी कर दिया है। अभी प्रदेश में भाजपा की सरकार है इसलिए भाजपा के बड़े नेता टिकटों के आवंटन के समय आप का रुख करेंगे। जबकि कांग्रेस के लोग पहले जाकर वहां पर अपना स्थान पक्का करने की नीयत से अभी जाने शुरू हो गये हैं। बल्कि एक सेवारत आईएएस अधिकारी दिल्ली जाकर केजरीवाल से मिल भी आये हैं और कभी भी नौकरी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश के जिन नेताओं के आप में जाने की चर्चाएं आम जुबान तक का आ गयी हैं उनमें महेश्वर सिंह, अनिल शर्मा, सुरेश चदेल, सुभाष मंगलेट, गंगूराम मुसाफिर, सोहन लाल, रणवीर निक्का और हरदीप बावा के नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। यह तय माना जा रहा है कि ऐसे लोगों के जाने से कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही ठोस नुकसान पहुंचेगा। वैसे तो जब तक हिमाचल के चुनाव होने हैं तब तक पंजाब में वहां की सरकार की परफॉरमैन्स भी सामने आ जायेगी और उसका भी हिमाचल में पार्टी के भविष्य पर एक असर पड़ेगा। लेकिन इसी दौरान जो कुछ और घटा है उसका भी पार्टी के गठन पर असर पड़ेगा यह भी तय है। स्मरणीय है कि चुनाव के दौरान यह आरोप लगा था कि आप को खालिस्तान समर्थकों का समर्थन भी हासिल है। खालिस्तान का नाम आप के साथ जुड़ने से उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर इन आरोपों की जांच किये जाने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने भी यह जांच करवाये जाने का आश्वासन दिया था। चुनाव परिणाम आप के पक्ष में आये और पंजाब में उसकी सरकार बन गयी। सरकार बनने के बाद पंजाब के कुछ लोग हिमाचल के मणिकरण और ज्वालामुखी में आये उनके वाहनों पर भिण्डरावाला के फोटो और खालिस्तान के कथित झंडे पाये गये। हिमाचल पुलिस ने इस पर एतराज किया और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के शायद मामले बना दिये। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी एक ब्यान देकर इस सब की निंदा की और प्रदेश में इसको सहन न करने की बात कही। हिमाचल की इस प्रतिक्रिया पर पंजाब के एन्ट्री स्थलों पर हिमाचल के वाहनों को रोक दिया गया। यही नहीं सिक्खों की शीर्ष संस्था सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एडवोकेट हरजिंदर सिंह के माध्यम से नोटिस भेज दिया। ब्यान वापस लेने और अफसोस जताने की मांग कर दी। बात यहीं नहीं रुकी खालिस्तान के गुरु यशवंत सिंह ने मुख्यमंत्री को सीधे धमकी दे दी कि 29 अप्रैल को वह शिमला में खालिस्तान का झंडा फहरायेंगे। पन्नू का धमकी का वीडियो वायरल हो चुका है। पूरा प्रदेश इसकी निंदा और विरोध करते हुये मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हो गया है। एन्टी टैरिस्ट फ्रन्ट के अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने ब्यान जारी करके इस धमकी की कड़ी निंदा करते हुये गृह मंत्री से मांग की है कि सरकार भिण्डरावाला का स्टेटस बताये कि वह आंतकवादी थे या नहीं। क्या उनका फोटो लगाना प्रतिबंधित है। स्मरणीय है कि इस आश्य की आर टी आई कई बार पहले भी डाली गयी है और यह पूछा गया है कि भिण्डरावाला संत थे या आतंकी। लेकिन इनका जवाब कभी नहीं आया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने यह आर टी आई पंजाब सरकार को भेज दी थी परंतु जवाब नहीं आया है। बल्कि लखीमपुर खीरी में भी एक प्रोटेस्टर की टी-शर्ट पर भिण्डरावाला का फोटो देखा गया था। 2003 में अकाल तख्त ने भिंडरावाला को शहीद घोषित कर दिया था। कुछ उन्हें आदर्श मानते हैं। भाजपा नेता डॉ. स्वामी उन्हें आतंकी नहीं मानते हैं। खरड निवासी नवदीप गुप्ता ने भिण्डरावाला पर आरटीआई डाली थी कि वह आंतकी थे या नहीं। इसका जवाब सरकार ने नहीं में दिया है। यही नहीं 2001 में जब संघ प्रमुख सुदर्शन जी और भाजपा नेता ए आर कोहली दमदमी टकसाल जाकर भिण्डरावाला के उत्तराधिकारी को मिले थे तब उन्होंने इस पर अफसोस जाहिर किया था। कुल मिलाकर आज भी सरकार इस पर स्पष्ट नहीं है कि भिंडरावाला को आतंकी माना जाये या शहीद संत।

यह चर्चा इसलिये आवश्यक हो जाती है कि हिमाचल की घटना के बाद प्रदेश की आप इकाई ने उसे शरारती तत्वों का कृत्य बताया था। लेकिन हिमाचल के वाहनों को रोके जाने पर पंजाब सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर बात पन्नू की धमकी तक आ गयी है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि जब तक सरकार की ओर से भिण्डरावाला का स्टेटस स्पष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक उनके फोटो को लेकर ऐतराज़ कैसे उठाया जा सकता है। बल्कि इस समय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वपल्ली सरदार बेअन्त सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर 30 अप्रैल तक फैसला लेने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिये हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब पंजाब में अकाली- भाजपा सरकार थी तब राजोआना की फांसी को यह कहकर टाल दिया गया कि इससे कानून और व्यवस्था का सवाल खड़ा हो जायेगा। अमरिंदर के शासन में यह मामला लटका रहा। इस संद्धर्भ में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब केंद्र इस पर क्या फैसला लेता है। क्योंकि इस सब का संबंध आतंकवाद के प्रति हमारी धारणा का घोतक हो जाता है। इस समय प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनकर आप आने का दावा कर रही है। इस दावे के परिपेक्ष में आप के खालिस्तान के साथ परोक्ष और अपरोक्ष रिश्तों को लेकर उठते सवालों को नजर में रखना आवश्यक हो जाता है।

# क्यों नहीं आ पाया कांग्रेस का आरोप पत्र उठने लगा है सवाल

**शिमला/शैल।** प्रदेश कांग्रेस में चार उपचुनाव जीतकर जो जोश का माहौल खड़ा हुआ था उसकी हवा पांच राज्यों में मिली हार से पूरी तरह निकल गयी है यहां एक कड़वा सच है। इसमें पंजाब में आप की जीत ने प्रदेश कांग्रेस के सारे पुराने समीकरण बिगाड़ कर रख दिये हैं। क्योंकि अभी कांग्रेस से ही ज्यादा लोग निकलकर आप में जा रहे हैं। जो कांग्रेस चारों उपचुनाव जीतकर अति उत्साहित होकर चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री कौन होगा की अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त हो गयी थी आज उसमें अपने ही कुनवे को संभाल कर रखने वाला कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं है। आज कांग्रेस में स्व. वीरभद्र की कमी को पूरा करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। आज कांग्रेस में इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि उसने जयराम सरकार के खिलाफ इन चार वर्षो में कौन सा बड़ा मुद्दा खड़ा किया है। यहां तक कि इस वर्ष ही पार्टी ने सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र लाने की घोषणा की थी। इसके लिये एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया था। माना जा रहा था कि यह आरोप पत्र इस बजट सत्र से पहले जारी हो जायेगा और सत्र में चर्चा में ला दिया जायेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। जयराम सरकार के कार्यकाल में आयी दो कैग रिपोर्टो में ही सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे हैं। लेकिन कांग्रेस इन रिपोर्टो पर भी कुछ नहीं कर पायी है। 2014 में कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय बताकर उससे सत्ता छीनी गयी थी। हिमाचल के हर चुनाव में भाजपा के सभी छोटे-बड़े नेताओं ने स्व. वीरभद्र के खिलाफ बने मामलों को खूब भुनाया था। लेकिन यह प्रदेश

शेष पृष्ठ 8 पर.....

# मुख्यमंत्री ने राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की

**शिमला/शैल।** राज्य सरकार प्रदेश में वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति सचेत हैं जिसके लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई

है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबद्ध विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर सभी विकासात्मक परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी परियोजनाओं की भी योजना बनाई जानी चाहिए जिन्हें पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि मेगा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्टस तैयार करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए, जिन्हें केंद्रीय वित्त पोषण के लिए भेजा किया जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वन्य जीवों का संरक्षण महत्त्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वन्यप्राणी क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मामलों के विकास कार्य बाधित न हों। उन्होंने अधिकारियों को थुनाग – पज्ता – लंबासफर – चिलमगढ़ – शिकारीदेवी से प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने दुर्लभ हिमालयी प्रजातियों के पशु – पक्षियों के संरक्षण के लिए ठोस योजना बनाए जाने पर भी बल दिया।

बैठक में मैसर्स प्रीमियर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांगड़ा जिले के औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टैरेस में ग्रेन बेसड डिस्टिलरी और सह – उत्पादन बिजली संयंत्र के विस्तार के मामले को राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड को अनुशंसित संस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया।

बोर्ड ने रकछम – छितकुल वन्यप्राणी अभयारण्य के भीतर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा नगासति में हेलीपैड के निर्माण के लिए 0.0375 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन को स्वीकृति प्रदान की तथा इसे राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड को अनुशंसित करने को स्वीकृति प्रदान की।

इस अवसर पर बोर्ड के गैर सरकारी एवं सरकारी सदस्यों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक का संचालन करते हुए पूर्व बैठक की कार्य सूची पर कार्यवाही की रिपोर्ट तथा वन्यप्राणी खण्ड की विभिन्न गतिविधियों पर प्रस्तुति भी दी। बंजार के विधायक तथा राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के सदस्य सुरेन्द्र शौरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन निशा सिंह, प्रधान मुख्य आरण्यपाल (वन बल प्रमुख) अजय श्रीवास्तव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

# वर्ष 2030 तक एचआईवी को समाप्त करने के लिए सभी को सामूहिक एवं ठोस प्रयास करने होंगे: स्वास्थ्य सचिव

**शिमला/शैल।** स्वास्थ्य सचिव एवं हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी के अध्यक्ष अमिताभ अवस्थी की अध्यक्षता में सोसायटी द्वारा अन्तर विभागीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एचआईवी गतिविधियों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए वर्ष 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने पर चर्चा की गई।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2030 तक एचआईवी को समाप्त करने के लिए सभी को सामूहिक एवं ठोस प्रयास करने होंगे। इसके लिए मौलिक विचारों के साथ आगे आना होगा और इच्छित परिणामों के लिए मिशन मोड में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि एचआईवी प्रभावित लोगों को पोषण सहायता उपलब्ध करवाने, कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने तथा एड्स प्रभावित बच्चों को गोद लेने जैसे विषयों पर विशेष परियोजना बनाई जानी चाहिए।

उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को नौवीं से 12वीं कक्षा के पाठयक्रम में एचआईवी से सुरक्षा सम्बन्धी अध्याय शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किशोरों एवं युवाओं को एचआईवी से सम्बन्धित सही जानकारी उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण है और इसमें रैड रिबन क्लब अपनी अह्म भूमिका निभा सकते हैं। राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 259 रैड रिबन क्लब हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश राज्य निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग को अपने अपने संस्थानों में रैड रिबन क्लब गठित करने और इनके माध्यम से जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सचिव ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को शैक्षणिक संस्थानों में युवा महोत्सवों के आयोजन के दौरान एचआईवी के प्रति जागरूकता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों और संगठनों को निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के आयोजन के दौरान एचआईवी सुरक्षा पर अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने स्वास्थ्य परिसरों में एचआईवी जांच सुविधा स्थापित करने को भी कहा।

इस मिशन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवाएं अधिकारी रूपाली ठाकुर की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया। इस समिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सदस्य शामिल किए जाएंगे।

# राज्य में स्थापित की जा रही हैं 59 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

**शिमला/शैल।** राज्य पेयजल एवं स्वच्छता संगठन के निदेशक व मुख्य अभियंता इंजीनियर जोगिंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग ने न केवल हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, बल्कि जल गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्वर्णिम जयंती कार्यक्रम की श्रृंखला में जून व अक्तूबर माह तथा अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर से 24 जनवरी तक शुद्ध जल अभियान चलाया गया, जिनमें कुल 90958 (जून माह में 22697 अक्तूबर माह में 42004 और 25 दिसंबर से 24 जनवरी तक 26257) जल नमूनों के परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से किए गए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग व कार्यन्वयन सहायता एजेंसी की सहभागिता से जल शुद्धता के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रयोगशालाओं व फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से लोगों को जल नमूना परीक्षण सिखाया जा रहा है।

निदेशक ने कहा कि जल जीवन मिशन के शुरू होने से पहले आमजन के लिए जल शुद्धता परीक्षण का फील्ड टेस्ट किट के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम नहीं था लेकिन अब जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर आमजन के लिए जल शुद्धता परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवा एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 59 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें 14 जिला स्तरीय, 45 उपमण्डल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। अब तक राज्य की 44 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय मानकों के आधार पर नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेटरी (एनएबीएल) से प्रमाणिकता मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भी स्थापित की जा रही है। जिसमें जल नमूनों के राष्ट्रीय ब्यूरो मानक के हिसाब से सभी भौतिक, रासायनिक व जीवाणु जल नमूनों के परीक्षण किए जाएंगे, जो शुद्ध जल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

# सरकार, प्रशासन और आम जनता के बीच एक सेतु है मीडिया:राजेंद्र चौधरी

**शिमला/शैल।** पीआईबी शिमला ने होटल हमीर में जिला के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों के लिए 'वार्तालाप' कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। जबकि, पत्र सूचना कार्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी

भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जिलाधीश ने कहा कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार, प्रशासन और आम जनता के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के साथ – साथ मीडिया इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार और प्रशासन को महत्वपूर्ण फीडबैक भी प्रदान करता है। जिलाधीश ने कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं आम नागरिक पर ही केंद्रित होती हैं और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकारी अधिकारियों के साथ – साथ मीडिया की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए प्रशासन और मीडिया में आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

'वार्तालाप' के आयोजन के लिए पीआईबी की सराहना करते हुए देबश्वेता बनिक ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से प्रशासन को मीडियाकर्मियों के साथ सीधा संवाद करने और उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में काफी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रैस विज्ञप्तियों के अलावा पीआईबी अन्य माध्यमों से भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार – प्रसार कर रही है। इसी कड़ी में सुजानपुर के होली उत्सव में भी पीआईबी ने मल्टी मीडिया प्रदर्शनी और फोक मीडिया के माध्यम से आम लोगों को जागरुक किया।

इस अवसर पर जिलाधीश, अन्य वक्ताओं और सभी पत्रकारों का स्वागत करते हुए पीआईबी के चंडीगढ़ कार्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मीडिया सरकार और आम जनता के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुचाने के लिए पीआईबी के चंडीगढ़ कार्यालय की ओर से जिला स्तर पर 'वार्तालाप' कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का काम कल्याणकारी योजनाएं बनाना और उनको लागू करना है, जबकि मीडिया इन योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाता है। इन योजनाओं के संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया सरकार तक पहुंचाने में भी मीडिया अपनी भूमिका अदा करता है। चौधरी ने कहा कि आज के दौर में डिजिटल मीडिया भी सूचनाओं के आदान – प्रदान का एक सशद्र माध्यम बन चुका है। अतिरिक्त महानिदेशक ने उपस्थित मीडियाकर्मियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पत्रकार कल्याण योजना के अलावा अन्य योजनाओं से भी अवगत करवाया।

उन्होंने कहा कि पीआईबी कार्यालय पत्रकारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनायेगा। इस ग्रुप में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और सफलता की कहानियां साझा की जाएंगी।

कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार डॉ. अशोक पठानिया ने मीडियाकर्मियों को केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना और जिला में इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सर्वे एवं अन्य प्रक्रियाओं की जानकारियां प्रदान कीं। उन्होंने बताया कि हिमाचल में जिला हमीरपुर में यह योजना पायलट आधार पर एक नवंबर 2021 से शुरू की गई है। जिला के 365 आबादी देह गांवों में इसका ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है।

इस अवसर पर जिला लोक संपर्क अधिकारी मीना बेदी ने 'वार्तालाप' कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया के साथ समन्वय स्थापित करने की दिशा में यह पीआईबी की बहुत ही अच्छी पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां मीडिया के साथ सीधा संवाद होगा, वहीं सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी मिलेगी।

'वार्तालाप' में अन्य योजनाओं और पत्रकारों से सूचना के आदान – प्रदान के संबंध में भी व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के बाद विभिन्न सत्रों के दौरान विभिन्न विषयों पर विचार – विमर्श किया गया। पीआईबी के शिमला कार्यालय के उपनिदेशक तारिक अहमद राठर ने कार्यक्रम का संचालन किया। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अहमद खान ने सभी आभार व्यक्त किया।

# कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

**शिमला/शैल।** तकनीकी शिक्षा मंत्री राम लाल मारकंडा की उपस्थिति में तकनीकी शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई के बीच प्रदेश के राजकीय आईटीआई के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर प्रदेश सरकार की ओर से तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चन्देल और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई की ओर से डॉ.पीके शुक्ला उपाध्यक्ष (सीएसआर और विशेष परियोजनाएं) ने हस्ताक्षर किए। डॉ. राम लाल मारकंडा ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षरित होने से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे माल, उपकरण और मशीनरी की खरीद और समय पर उनकी उपलब्धता की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक सुनील वर्मा, उप – निदेशक प्रशिक्षण संजय गुप्ता, राजकीय आईटीआई सुन्दरनगर के प्रधानाचार्य आदित्य रैना सहित अन्य उपस्थित थे।

# मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों के रख-रखाव की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला से लोक निर्माण विभाग की बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सड़कों की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अधिकारियों विशेषकर मुख्य अभियन्ताओं तथा अधीक्षण अभियन्ताओं को नियमित रूप से फील्ड का दौरा कर प्रदेश की सड़कों के रख-रखाव की प्रगति की समीक्षा के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य अभियन्ता अपने जोन में हो रहे सड़कों के रख-रखाव की प्रगति की निरंतर निगरानी कर उच्च अधिकारियों को समय-समय पर इस सम्बन्ध में सूचित करते रहें। उन्होंने कहा कि सड़कों को पक्का करने के कार्यो की निविदाओं में किसी भी प्रकार के विलम्ब को गम्भीरता से लिया जाएगा तथा इसके दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो।

जय राम ठाकुर ने सड़कों को प्रदेश की जीवन रेखाओं की संज्ञा देते हुए कहा कि पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रदेश में आवागमन के सीमित साधन हैं, जिसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार सड़क निर्माण तथा इसके रख-रखाव पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर नवीनीकरण, पैचवर्क और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड और अन्य सड़कों की टारिंग करके सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए गम्भीर प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने राज्य और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से वार्षिक रख-रखाव योजना 2021-22 के अन्तर्गत 75 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जिस पर 228 करोड़ रुपये खर्च कर 1798 किलोमीटर सड़कों पर कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के रख-रखाव और अन्य संबंद्ध गतिविधियों के लिए वार्षिक रख-रखाव योजना 2022-23 के अन्तर्गत 1950.59 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बिटुमिन गतिविधियों के लिए राज्य में 131 संयंत्र हैं, जिनमें से 63 संयंत्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को शेष संयंत्रों को शीघ्र अति शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

प्रधान सचिव लोक निर्माण सुभासीष पंडा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि निर्धारित समयावधि में लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव राम सुभग सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे जबकि विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं ने वर्चुअल माध्यम से अपने-अपने स्थान से बैठक में भाग लिया।

# पीएम-जीकेएवाई के अंतर्गत सितम्बर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) को अगले छः माह यानि सितम्बर, 2022 तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। यह इस योजना का छठा चरण होगा।

इस योजना का पांचवा चरण मार्च, 2022 में समाप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल, 2022 से पीएम-जीकेएवाई के रूप में देश में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये व्यय किए हैं और अगले छः महीनों यानि सितम्बर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये व्यय किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम-जीकेएवाई के अंतर्गत होने वाला कुल व्यय लगभग 3.40 लाख करोड़ होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना के अंतर्गत भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेशवासी भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम- जीकेएवाई के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न के सामान्य कोटे के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त पांच किलोग्राम निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा, अर्थात हर गरीब परिवार को सामान्य राशन से लगभग दोगुना राशन मिलेगा।

# प्रदेश में केवल पंजीकृत ठेकेदारों के पक्ष में ही जारी होंगे मछली आयात के परमिट:वीरेन्द्र कंवर

**शिमला/शैल।** ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से मत्स्य विभाग द्वारा प्रदेश में मछली आयात के परमिट केवल पंजीकृत ठेकेदारों के पक्ष में ही जारी किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जलाशयों के मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए व उनके रोजगार क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रदेश के सभी जिलों में मछली आयात को आंशिक रुप से प्रतिबन्धित किया जा रहा है।

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 10 हजार परिवार मात्स्यिकी व्यवसाय से जुड़े हैं। प्रदेश के ठण्डे पानी, नदीय क्षेत्रों, तालाबों व जलाशयों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मत्स्य पालन हो रहा हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य जलाशय महाराणा प्रताप पौंग डैम व गोबिन्द सागर जलाशय से लगभग 5500 परिवार मछली पकड़ने के व्यवसाय से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों से मछली आयात के परमिट के लिए आवेदन विभाग के पास पहुंचते हैं। विभाग आवेदनकर्ताओं की मांग अनुसार मछली आयात का परमिट उस वित्तीय वर्ष के लिए उनके पक्ष में जारी करता है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के मछुआरों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तथा मत्स्य विभाग का राजस्व भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि परमिट प्राप्त होने पर लोग बाहरी राज्यों से कोल्ड स्टोर में रखी गई पुरानी मछली लाकर कम दामों पर बेच रहे हैं। इस प्रकार की पुरानी मछली की गुणवत्ता ताजा मछली की अपेक्षा बहुत कम होती है क्योंकि प्रदेश के जलाशयों से जो मछली पकडी जाती है वह ताजा व पौष्टिक होती है।

प्रदेश के जलाशयों में मछली की अच्छी प्रजातियां उपलब्ध होने के बावजूद मछली के अच्छे दाम बाजार में नहीं मिल रहे हैं, जिसका मुख्य कारण प्रदेश में अधिक मात्रा में नियमित रूप से मछली का आयात किया जाना है। इससे आजीविका के लिए केवल मछली पालन पर ही निर्भर प्रदेश के 5500 से अधिक मछुआरों की रोजी-रोटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में मछली व्यवसाय से जुड़े सभी व्यापारियों, पंजीकृत ठेकेदारों तथा मछुआरों व मत्स्य सहकारी सभाओं के हितों के दृष्टिगत मछली आयात पर आंशिक प्रतिबन्ध संबंधी यह निर्णय लिया गया है तथा भविष्य में इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त मत्स्य विभाग से मछली आयात का परमिट लेने के सभी नियमों को भी सरल बनाया जाएगा।

# मुख्यमंत्री ने एनटीईपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण वर्ष 2021 के दौरान बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्वेक्षण भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय टीबी प्रभाग द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है।

जय राम ठाकुर ने प्रदेश की जनता से क्षय रोग के उन्मूलन के लिए सहयोग करने का आग्रह किया ताकि क्षय रोग मुक्त हिमाचल की परिकल्पना साकार हो सके। उन्होंने राज्य से इस बीमारी को समाप्त करने के लिए जन प्रतिनिधियों, चिकित्सकों, गैर सरकारी संगठनों और जन सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए राज्य और जिला स्तरीय उप राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया है। वर्ष 2021-22 के लिए हिमाचल प्रदेश में सब नेशनल सर्टिफिकेट के लिए राज्य के सभी 12 जिलों को नामांकित किया गया था, जिसमें राज्य के 8 जिले हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, लाहौल-स्पिति और ऊना को रजत पदक, जबकि चम्बा, सिरमौर व सोलन जिलों को कांस्य पदक से सम्मानित किया जाएगा।

# मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कैम्पा की 5वीं संचालन समिति की बैठक आयोजित

**शिमला/शैल।** मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की 5वीं संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में चौथी संचालन समिति की कार्रवाई की समीक्षा की गई और वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना के विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वनों में हो रहे अवैध कटान, अवैध खनन, अतिक्रमण आदि की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग में इन अपराधों को रोकने के लिए विभाग के चुनिंदा फ्रंट लाईन स्टाफ को ड्रोन कैमरों को प्रयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाये व ड्रोन कैमरों के माध्यम से वनों की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया आगामी बैठक से पूर्व तैयार की जाये। ड्रोन कैमरों की खरीद व फ्रंट लाईन स्टाफ के प्रशिक्षण पर कैम्पा में अतिरिक्त बजट का प्रबन्ध भी किया जाये। उन्होंने कैम्पा के तहत वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना की कार्य सूची को तय समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा राजेश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण के तहत वन विभाग में गत तीन वर्षो के दौरान किए गए कार्यो व वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना की कार्य सूचि को संचालन समिति के समक्ष रखा। वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत पौधरोपण, नर्सरी प्रबन्धन, लैन्टाना उन्मूलन, वनों की आग की रोकथाम, जल व मृदा संरक्षण जैसे कार्यो के अतिरिक्त डिफरेंशियल ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम के माध्यम से वनों का सर्वेक्षण, सीमांकन और वन सीमाओं का भू-सन्दर्भ जैसे कार्यो को वेबसाईट पर अपलोड करना शामिल है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वन निशा सिंह, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफसीए) राकेश गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (प्रबन्धन) डॉ. सुशील कापटा, मुख्य अरण्यपाल वन्यप्राणी (दक्षिण) शिमला के.थीरूमल, वन मण्डल अधिकारी (ईको-टूरिज्म/कैम्पा) प्रीति भण्डारी व राजस्व, कृषि विभाग, जनजातीय विकास विभाग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

# किसानों को विभिन्न योजनाओं के सभी लाभ समयबद्ध उपलब्ध करवा रही प्रदेश सरकार

**शिमला/शैल।** कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार विभाग के माध्यम से किसानों को विभिन्न योजनाओं के सभी लाभ समयबद्ध उपलब्ध करवा रही है।

उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों, एंटी हेल नेट, टिल्लर इत्यादि पर अनुदान पात्र किसानों को प्रदान किया जा रहा है। कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अन्तर्गत फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को एंटी हेल नेट्स की खरीद पर 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 8 करोड़ 29 लाख रुपये व्यय कर विभिन्न जिलों के 2,395 किसानों को लाभान्वित किया गया है तथा 39 लाख 24 हजार 589 वर्ग मीटर क्षेत्र इसके अन्तर्गत लाया गया है। जिन किसानों को एंटी हेल नेट खरीद की स्वीकृति दी गई है, उन्हें अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत लम्बित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहाड़ी खेती के मशीनीकरण के लिए किसानों को बड़े स्तर पर पावर टिल्लर व अन्य कृषि उपकरण उपदान पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इसमें 15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अनाज तथा सब्जियों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और नवीनीकरण मौसम आधारित फसल बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है। प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान का तुरंत मुआवजा देने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2016 मौसम से रबी 2020-21 मौसम तक 3,82,777 किसानों को 74.20 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान करके लाभान्वित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि खाद, बीज, कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाओं पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान प्रदान किया जा रहा है। किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में गेहूं और मक्की के बजट में बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2020-21 में भी विभाग द्वारा किसानों को मक्की बीज निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाया गया। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मक्का पर 40 रुपये व गेहूं पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम या 50 प्रतिशत की दर से किसानों को अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को उत्तम किस्म का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत विभाग फफूंदनाशक व कीटनाशक पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा 17.87 मीट्रिक टन फफूंदनाशक तथा 5.74 मीट्रिक टन कीटनाशक किसानों को इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान पर उपलब्ध करवाया गया।

**अग्नि के समान तेजस्वी जानकर ही किसी का सहारा लेना चाहिए।।**

.....चाणक्य

## सम्पादकीय

# जीत का उपहार महंगाई क्यों

चुनाव परिणामों के बाद एक पखवाड़े के भीतर ही पैट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ गये हैं। 800 दवाइयों के दाम 1 अप्रैल से बढ़ने का समाचार आ चुका है। इसका असर अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर भी पड़ेगा। यह निश्चित है देश से विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब डॉलर कम हो गया है। रिलायंस ने अपने पेट्रोल पम्प बंद करने का ऐलान कर दिया है। वर्ष 2022–23 के बजट में मनरेगा, ग्रामीण विकास, जल जीवन, फसल बीमा और पीडीएस के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कटौती की गयी है। इस कटौती का परिणाम भी महंगाई और बेरोजगारी के रूप में सामने आयेगा ही। जैसे–जैसे यह महंगाई तथा बेरोजगारी बढ़ती जायेगी उसी अनुपात में सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चायें बढ़ेंगी। इन चर्चाओं को अन्य मुद्दे रोक नहीं पायेंगे। जिस विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मानती थी। आज उसमें एकदम 9 अरब डॉलर की कमी आने से सारा परिदृश्य ही बदल गया है। जब गांव और रक्षा से जुड़े बजट में ही सरकार को कटौती करनी पड़ जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रचारित किया जा रहा है सच उससे कहीं अलग है।

मोदी सरकार का सबसे पहला और बड़ा फैसला नोटबंदी का आया था। नोट बन्दी लाने के जो कारण और लाभ बताये गये थे उनका सच इसी से सामने आ जाता है कि99. 6% पुराने नोट नये नोटों से बदला दिये गये। इसका अर्थ है कि काले धन के जो आंकड़े और इसके आतंकवाद में लगने के जो आंकड़े परोसे जा रहे थे वह सब काल्पनिक थे। केवल सत्ता परिवर्तन का हथियार बनाये जा रहे थे। इसी काले धन से हर बैंक खाते में 15 लाख आने का सपना दिखाया गया था। इस नोटबंदी से जो अद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुये वह सरकार के पैकेज से भी पुन:जीवित नहीं हो सके हैं। नोट बंदी के कारण बड़े क्षेत्र का उत्पादन प्रभावित हुआ जिससे महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। इसी नोटबंदी के बाद बैंकों में हर तरह से के जमा पर ब्याज दरें घटाई और हर सेवा का शुल्क लेना शुरू कर दिया। इसी का परिणाम है कि जीरो बैलेंस जनधन खातों पर पांच सौ और हजार के न्यूनतम बैलेंस की शर्त लगा दी गई। नोटबंदी से हर व्यक्ति और हर उद्योग प्रभावित हुआ। लेकिन आम आदमी इसके प्रति चौकन्ना नहीं हो पाया। क्योंकि उसके सामने गौरक्षा, लव जिहाद, तीन तलाक, नागरिकता संशोधन कानून, राम मन्दिर और धारा 370 जैसे मुद्दे परोस दिये गये। लेकिन इन मुद्दों से चुनाव तो जीत लिये गये परंतु इन से अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाया। अर्थव्यवस्था को सबसे घातक चोट कोरोना के लॉकडाउन में पहुंची। जब सारा उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। स्वभाविक है कि जब उत्पादन ही बंद हो जायेगा तो उसका असर निर्यात पर भी पड़ेगा। इसी का परिणाम है विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट आ गयी है।

इस समय जिस ढंग से सरकार ने सार्वजनिक संपत्तियों को निवेश के नाम पर प्राइवेट सैक्टर को सौंपना शुरू किया है उसका अंतिम परिणाम महंगाई और बेरोजगारी के रूप में ही सामने आयेगा। यह एक स्थापित सत्य है कि जब कोई सरकार सामान्य जन सेवाओं को भी निजी क्षेत्र के हवाले कर देती है तो उससे गरीब और अमीर के बीच का अन्तराल इतना बढ़ जाता है कि उसे पाटना असंभव हो जाता है। आज सरकार अपनी आर्थिक नीतियों पर बहस को कुछ अहम मुद्दे उभार कर दबाना चाह रही है। जैसे ही दामों की बढ़ौतरी हुई तो उससे ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर फाइल जैसी फिल्म का मुद्दा परोस दिया गया। यहां तक कि स्वयं प्रधानमंत्री इस फिल्म के प्रचार पर उतर आये। अब यह आम आदमी को सोचना होगा कि वह इस फिल्म के नाम पर महंगाई और बेरोजगारी के दंश को भूल जाता है या नहीं। अभी फिर चुनाव आने हैं और इनसे पहले यह फिल्म आ गयी है। इसका मकसद यदि राजनीति नहीं है तो इसे यू टयूब पर डालकर सबको क्यों नहीं दिखा दिया जाता। कश्मीरी पंडितों के अतिरिक्त और भी कईयों के साथ ऐसी ज्यादतियां हुयी हैं। उन पर भी फिल्में बनी जिन्हें रिलीज नहीं होने दिया गया है। ऐसे में यदि इस फिल्म को महंगाई और बेरोजगारी पर पर्दा डालने का माध्यम बना दिया गया तो फिर कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं रह जायेगा।

# सूफियों की शिक्षा से सीख लें नहीं तो बिखड़ जाएगा हिन्दुस्तान

गौतम चौधरी

कर्नाटक से उठा हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी देखते ही देखते अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर लिया। इसे वैश्विक बनाने की भी कोशिश की गयी है। अभी हाल ही में मुस्लिम देशों के एक प्रभावशाली संगठन ने भारत में हो रहे हिन्दू–मुस्लिम विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मसलन, इसे वैश्विक रूप देने की भी कोशिश जारी है। यही नहीं चंद मौकापरस्थों और राजनीतिक अवसरवादियों ने कर्नाटक के समाज को दो धड़ों में बंट दिया है। एक पक्ष हिजाब की मुखालफत करता है। वहीं दूसरा खेमा हिजाब का पक्षधर है, उनके साथ अपने को सेक्युलर कहने वाले भी खड़े हो गए हैं। साफ तौर पर कर्नाटक, समाज हिंदू बनाम मुस्लिम में विभाजित हो चुका है। यह हिजाब का विवाद यही नहीं रुक रहा है। अब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और ऐसा बहुत कुछ किया जा रहा है जो न केवल एक देश के रूप में भारत की अखंडता और एकता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सीधे सीधे एक एजेंडे के तहत बदले की राजनीति में परिवर्तित होता जा रहा है।

कर्नाटक पुलिस ने कलबुर्गी जिले के अलंद में बीते एक मार्च को हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद 167 लोगों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक में तनाव का ताजा केंद्र कलबुर्गी है, जहां विवाद के केन्द्र में शिवलिंग और दरगाह है। 2022 के मार्च में कर्नाटक के कलबुर्गी में सांप्रदायिक तनाव को 2021 के सांप्रदायिक तनाव से जोड़ा जा रहा है। बता दें कि कलबुर्गी के अलंद में लाडले मशक साहब की एक दरगाह है। उसी परिसर में राघव चौतन्य शिवलिंग भी है। बात नवंबर 2021 की है आरोप लगा था कि मुसलमानों ने शिवलिंग को अपवित्र कर दिया। कलबुर्गी के हिंदूवादी संगठन कथित अपवित्रता के चलते शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए 1 मार्च 2022 को विशेष पूजा अर्चना करना चाहते थे। उसी दिन मुस्लिम संप्रदाय ने भी परिसर में मौजूद दरगाह पर शबाब–ए– बारात कार्यक्रम करने की तैयारी कर दी। महाशिवरात्रि का मौका था इसलिए बात आगे न बढ़े और किसी तरह का कोई बवाल न हो इसलिए पुलिस और जिला प्रशासन ने इलाके में 27 फरवरी से 3 मार्च तक धारा 144 लगाकर लोगों के एकसाथ जमा होने पर पाबंदी लगा दी।

सच पूछिए तो कलबुर्गी बेहद शांत क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र को साम्प्रदायिक सहिष्णुता के रूप में पेश किया जाता रहा है। आज यहां के मजार को विवादित बताया जा रहा है लेकिन यह मजार हिन्दू–मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। आज से लगभग 600 साल पहले एक सूफी संत, हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी को एक देशमुख द्वारा कर्नाटक के कलौरगी जिले के अलंद में कुछ जगह उपलब्ध कराई गयी थी। साथ ही संरक्षण भी दिया गया था। सूफी संत यहीं रह गए और लोगों के बीच शांति एवं सद्भाव का प्रचार करने लगे। सूफी संत की ख्याति बढ़ने लगी और दूर–दूर से लोग यहां आने लगे। परिवार जिसने संत को संरक्षण दिया, बाद में वह भी उनका मुरीद हो गया। सूफी संत का कब्रिस्तान भी वहीं बना दिया गया। उनके कब्र पर सालाना कार्यक्रम होने लगे और उनकी लोकप्रियता और बढ़ती चली गयी। सूफी संत स्थानीय लोगों के बीच लाडले मशक के नाम से मशहूर हो गए। कई वर्षों बाद कब्र को दरगाह का रूप दे दिया गया, जहां हर धर्म के मानने वाले पहुंचने लगे। लाडले मशक दरगाह के अलावा, कलबुर्गी जिले में सूफी संत के दरगाहों की अच्छी संख्या है। इन दरगाहों ने लबे समय तक हिंदू–मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में मदद की है। सूफीवाद अपनी शांतिपूर्ण शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। सूफियों को शांति, प्रेम के राजदूत के रूप में देखा जाता है। इस्लाम में दया, सद्भाव, धैर्य, सहिष्णुता आदि जो देखने को मिलता है उसमें सूफियों की बड़ी भूमिका है। सूफियों ने हमेशा मुसलमानों और गैर–मुसलमानों के प्रति समान रूप से नरम और कोमल व्यवहार का प्रदर्शन किया है। सुफियों की सबसे बड़ी खासियत कि वे सबसे उपर मानवता को महत्व देते हैं और सभी सूफियों के लिए माफी और पश्चाताप की संस्कृति को पेश करते हैं। अपने अनुयायियों को मानवता से प्यार करना सिखाते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने और आध्यात्मिक सभाओं के माध्यम से उग्रवाद, बुरे विचार, कृत्यों को हतोत्साहित करने की प्रेरणा देते हैं। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में, जिसने विभिन्न संस्कृतियों के सार तत्वों को अपने में समावेशित किया है, सूफियों ने इसे अपनी पहचान और परंपरा का अंग बना लिया।

कलबुर्गी के निवासियों को इतिहास से सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि साम्प्रदायिक दुराग्रह से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है। जरा सोचिए, शांतिपूर्ण माहौल को सांप्रदायिक बनाने से किसे फायदा होगा? इससे सांप्रदायिक ताकतों की योजनाएं सफल होगी। शांति को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी न केवल सूफियों पर है, बल्कि नागरिक समाज पर भी है, जिसे संचार के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके सामूहिक पहल करनी है और लोगों को लामबंद करना है। हमारे समाज की व्यापक भलाई के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हम यदि इस प्रयास में विफल हुए तो हमारी दुर्गति अफगानिस्तान, म्यांमार, इराक और सीरिया जैसे होगी। इसलिए प्रेम और सदभाव से समस्या का समाधान करें। साम्प्रदायिक शक्तियों को हतोत्साहित करें। इसी में सबका कल्याण है।

# सहकारिता के रास्ते ग्रामीण भारत में विकास को बढ़ावा

– हेमा यादव –
निदेशक, वैमनिकोम

वर्ष 1904 में भारत में पहला सहकारिता कानून लागू होने के बाद से भारतीय सहकारी संगठन अब तेज गति के बदलाव के लिए तैयार हैं। सहकारिता के क्षेत्र में नए प्रतिमानों और सहकारी संगठनों के लिए बजटीय आवंटन के साथ अलग से एक सहकारिता मंत्रालय की मौजूदगी के रूप में इसके बदलते स्वरूप के साथ विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में भारत के सहकारिता आंदोलन में एक नए सिरे से रुचि बढ़ी है।

अलग–अलग समय पर, विशेष रूप से नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) तक, बदलाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले सहकारी मॉडल ने भारत की विकास योजना की सफलता में अहम योगदान दिया है। गरीबी उन्मूलन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, सामाजिक एकीकरण और रोजगार सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में इसके अंतर्निहित लाभ हुए हैं। सहकारी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जिसकी ऋण और गैर–ऋण समितियों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण भारत में व्यापक पहुंच है। भारत की कुल 8.5 लाख सहकारी इकाइयों में से, लगभग 20 प्रतिशत (1.77 लाख इकाइयां) (ऋण संबंधी सहकारी समितियां हैं और शेष 80 प्रतिशत गैर–ऋण सहकारी समितियां हैं, जोकि लगभग नब्बे प्रतिशत गांवों को कवर करती हुई मत्स्य, डेयरी, उत्पादक, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, पर्यटन, अस्पताल, आवास, परिवहन, श्रम, खेती, सेवा, पशुधन, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां आदि जैसी विविध गतिविधियों में शामिल हैं। सदस्यता के संदर्भ में अगर बात करें, तो लगभग दो सौ नब्बे मिलियन किसान सहकारी समितियों में नामांकित हैं। इनमें से 72 प्रतिशत किसान ऋण संबंधी सहकारी समितियों और 28 प्रतिशत किसान गैर–ऋण संबंधी सहकारी समितियों से जुड़े हैं (एनसीयूआई, 2018)।

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (पैक्स) देश की अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) से संबंधित निर्माण खंड हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 31 मार्च 2018 तक कुल 6,39,342 गांवों को कवर करते हुए 13.2 करोड़ सदस्यों के साथ देश में कुल 95,238 पैक्स उपलब्ध थे। ये समितियां गांवों में किसानों और निम्न–आय वर्ग के लोगों की वित्तीय सहायता करके उनके वित्तीय सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

एक अच्छे नेटवर्क और पैक्स जैसे संस्थानों की जरूरत होने के बावजूद, पैक्स के माध्यम से धीमी गति से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) का कहना है कि सहकारी समितियां स्वयं सहायता, आत्म–जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, हिस्सेदारी और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित होती हैं। अपने संस्थापकों की परंपरा में, सहकारी समितियों के सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल जैसे नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सहकारिता के मूल सिद्धांत से समझौता किए जाने की वजह से वित्तीय और गैर–वित्तीय सेवाओं के वितरण में गिरावट आई है। ऋण चुकता करने के क्रम में अपर्याप्त धन संबंधी चूक, पेशेवर मानव संसाधनों की कमी और तकनीक के धीमे समावेश के परिणामस्वरूप प्रबंधन संबंधी सूचना की खराब प्रणाली, पारदर्शिता, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में शिथिलता, कदाचार की समस्याएं पैदा हुई है जिसके कारण विकास की प्रक्रिया में रुकावट आई है।

एक बहुउद्देशीय समिति के रूप में पैक्स

मेहता समिति (1937) ने बढ़ते संकट और असंतोष को दूर करने के लिए सहकारी ऋण समितियों को 'बहुउद्देश्यीय' सहकारी समितियों के रूप में पुनर्गठित करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा, आजादी से पहले के काल में, सर मणिलाल नानावटी की अध्यक्षता वाली कृषि ऋण संगठन समिति ने सहकारी समितियों को एक व्यावहारिक व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए कृषि वित्त में राजकीय सहायता और सभी सहकारी ऋण समितियों को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में बदलने पर जोर दिया था और इस संबंध में सिफारिश की थी।

सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को सिर्फ एक ऋण समिति के बजाय एक ऐसी बहु–धंधी समिति के रूप में प्राथमिकता दी है जोकि ऋण एवं विभिन्न सेवाओं के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य कर सके। पुनरुद्धार की यह प्रक्रिया पैक्स को सेवा संगठनों के रूप में एक नई दिशा देने और कृषि विपणन, बागवानी, खाद्य तेल, उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास, प्राकृतिक खेती आदि से संबंधित कृषि बजट 2022–23 की विभिन्न योजनाओं के साथ एकीकृत करने का भी आहवान करती है। खरीद, भंडारण एवं वेयरहाउसिंग, प्रसंस्करण, ग्रामीण एवं कृषि संबंधी लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन, बाजार संबंधी परामर्श एवं खुफिया जानकारी आदि जैसी गतिविधियों पर अमल कर पैक्स को बहुउद्देशीय समितियों के रूप में मजबूत किया जाएगा। हालांकि वर्तमान की बाजार एवं प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों के प्रमुख सिद्धांतों के रूप में 'सदस्यों की आर्थिक भागीदारी' और 'सहकारी समितियों के बीच परस्पर सहयोग' की केंद्रीयता बनाए रखने की जरूरत है।

पैक्स का डिजिटलीकरण

पैक्स का डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने और व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहारिक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। केन्द्रीय बजट 2022–23 में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा 63000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना तैयार की गई है।

पैक्स का डिजिटलीकरण कृषि संबंधी कई पहलों के कार्यान्वयन में सहायता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को डिजिटल समावेशिता के माध्यम से पारदर्शी तरीके से ऋण, उर्वरक और बीज प्राप्त हों। पैक्स में प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण किया जाना भी बेहद जरूरी है।

सहकारिता के इस डिजिटल ब्रह्मांड में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी और स्थायी रूप से प्रदर्शन करने के लिए पैक्स द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में विविधता लाना, नवाचार करना, ज्ञान साझा करने में सहयोग करना और उभरती हुई तकनीक का उपयोग किया जाना बेहद जरूरी है। बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन तकनीक जैसे उद्योग 4.0 के विभिन्न पहलू वितरण संबंधी आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता और विश्वास का समावेश करते हैं। मसालों, मत्स्यपालन, काजू और केसर, जोकि सहकारी समितियों के सदस्यों की अच्छी भागीदारी के साथ उच्च मूल्य वाले और निर्यात–उन्मुखी उत्पाद हैं, की आपूर्ति श्रृंखला में ब्लॉकचेन तकनीक का समावेश करने का यह सही समय है। पैक्स के सदस्यों के निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना समय की मांग है। पैक्स के डिजिटलीकरण के क्रम में विभिन्न संस्थानों द्वारा केएपी (ज्ञान, दृष्टिकोण व्यवहार) को अपनाए जाने की जरूरत है जोकि प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ–साथ अपेक्षित परिणाम की दिशा में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का समावेश करेगा।

सहकारी समितियों को किया गया बजट आवंटन विकास और समृद्धि के संचालक के रूप में सहकारी समितियों की ओर ध्यान केन्द्रित किए जाने को दर्शाता है। नवाचारों, उद्यमशीलता और प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए, यह बजटीय आवंटन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि कैसे पिरामिड के सबसे निचले हिस्से से विकास को ऊपर की ओर ले जाया जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कपड़ा, छोटे एवं मध्यम उद्यमों, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव और एकीकरण को आगे बढ़ाया जाए।

# सूअर पालन से प्रदेश की आर्थिकी को मिल रहा है बढ़ावा

**शिमला।** प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दे रही है। पशुधन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश सरकार ने पशुधन उत्पादन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सूअर पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अन्तर्गत लोगों को आजीविका के स्थाई अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए हैं। एनएलएम के अन्तर्गत ग्रामीण पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन व नस्ल सुधार के साथ–साथ इनके लिए उत्तम चारे की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जा रहा है।

प्रदेश के युवाओं के लिए आजीविका के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण बैकयार्ड विकास योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस केंद्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवार से संबंधित सूअर पालकों को 95 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसमें 90 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र तथा पांच प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जा रही है। सूअर पालकों को 95 प्रतिशत सब्सिडी पर तीन मादा और एक नर सूअर प्रदान किए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को कुल लागत की केवल पांच प्रतिशत की राशि ही वहन करनी पड़ती है। तीन से चार माह आयु वर्ग की स्वस्थ युवा मादा सूअर तथा चार से पांच माह आयु वर्ग के नर सूअर का बीमा भी करवाया जाता है।

राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन, छोटे और सीमान्त किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों से संबंधित किसानों, अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति से संबंधित बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है और योजना के लाभार्थियों में कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत उन परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जिनके परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत नही हैं और जिन किसानों के पास स्वयं के सूअर शैड अथवा मनरेगा के अन्तर्गत निर्मित सूअर शैड की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत पड़ोसी राज्यों से सूअर इकाइयों की व्यवस्था की जाती है। पात्र किसान पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से अपनी मांग रख सकते हैं और लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2019 में करवाई गई 20वीं पशुधन गणना के अनुसार प्रदेश में 2124 सूअर हैं। वर्ष 2019–20 में प्रदेश सरकार द्वारा 3.39 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई और पात्र लाभार्थियों को 20 सूअर इकाइयों वितरित की गई। वर्ष 2021–22 में 397.95 लाख रुपये व्यय कर 1995 सूअर इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनका कार्य प्रगति पर है।

राज्य सरकार द्वारा पशुपालन का कार्य कर रहे लोगों से वैकल्पिक आजीविका के रूप में सूअर पालन को अपनाने का आग्रह किया गया है।

# भारत का पहला एसएआई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिमला में स्थापित होगा

**शिमला।** युवा मामले और खेल मंत्रालय हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से माउंटेन टेरेन बाइकिंग में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत का पहला एसएआई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए तैयार है। शिमला में साइकिल मोटोक्रॉस, भारतीय साइकिल चालकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने के लिए एनसीओई की स्थापना की जा रही है ताकि वे एमटीबी और बीएमएक्स के विषयों में 18 ओलंपिक पदक के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें।

समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, दुनिया में सबसे अच्छी ऊंचाई प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक, इस केंद्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, एक अत्याधुनिक खेल विज्ञान उच्च प्रदर्शन केंद्र, ओलंपिक–स्तरीय ट्रैक और कोच होंगे। अंतरराष्ट्रीय ख्याति का, जहां भारत के सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालक और स्थानीय खेल प्रतिभा प्रशिक्षण ले सकते हैं। पहाड़ी इलाकों के लिए खेल की आवश्यकता और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण के कारण, शिमला एनसीओई के लिए एक पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरा।

इस साई एनसीओई की स्थापना के साथ, हिमाचल भारत में एमटीबी और बीएमएक्स प्रशिक्षण का पथप्रदर्शक बन गया है और दो साइकिलिंग विषयों के लिए भविष्य की विश्व चौंपियनशिप के लिए एक संभावित स्थल बन गया है। एनसीओई, जिसमें ओलंपिक स्तर की तैयारियों के लिए लगभग 200 साइकिल चालकों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी, 1 एक्ससीओ ओलंपिक स्तर ट्रैक, विशेष सुविधाओं के साथ 1 प्रशिक्षण ट्रैक, 1 बीएमएक्स ट्रैक, 1 अत्याधुनिक इनडोर व्यायामशाला से लैस होगा।

आभासी प्रशिक्षकों के साथ एक इनडोर सेटअप, 100 एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मचारियों के लिए छात्रावास की सुविधा। इसके अलावा, इनडोर रिकवरी पूल, स्ट्रीम और सौना, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग हॉल, बायोमेच लैब, फिजियोथेरेपी, एंथ्रोपोमेट्री जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ खेल विज्ञान के लिए एक उच्च प्रदर्शन केंद्र होगा। एथलीटों को उनके प्रशिक्षण के दौरान उपयोग करने के लिए सांस और लैक्टिक विश्लेषक, हृदय गति मॉनीटर, ट्रेडमिल, साइकिल एर्गोमीटर जैसे उच्च अंत उपकरण भी उपलब्ध होंगे।

23 मार्च, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ इस विश्व स्तरीय सुविधा को स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया था।

# मुख्यमंत्री ने नालागढ़ हेरिटेज पार्क में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन जिला के नालागढ़ में शहीदी दिवस के अवसर पर कृतज्ञ प्रदेशवासियों की ओर से भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नालागढ़ हेरिटेज पार्क में नालागढ़ हेरिटेज सोसायटी द्वारा जनसहयोग से निर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण भी किया। नालागढ़ में जन सहभागिता से निर्मित इस हेरिटेज पार्क के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

उन्होंने इस अवसर पर नालागढ़ उपमण्डल के 08 शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश उन वीर सेनानियों का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की शहादत ने जन-जन के मन में क्रान्ति और साहस की ऐसी अलख जगाई कि आज देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त भी यह विभूतियां युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज इन तीन क्रान्तिकारियों की स्मृति में हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। उन्होंने जन-जन का आहवान किया कि इन महान क्रान्तिकारियों के आदर्शो को जीवन में उतारें। यही सभी क्रान्तिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि स्वतन्त्रता संग्राम में हिमाचल के वीरों का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि शहीदों के जीवन से प्रेरणा लें और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग का सदैव अनुसरण करें। मुख्यमंत्री

ने हेरिटेज पार्क का निरीक्षण किया और इसके रखरखाव के सम्बन्ध में उचित दिशा-निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री ने अवसर पर वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद रामसरण के, वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद प्रदीप सिंह के, वर्ष 2002 के ऑपरेशन पराक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद जसविन्द्र सिंह के, वर्ष 2003 के ऑपरेशन पराक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद सुरेन्द्र सिंह तथा शहीद रामरत्न के, वर्ष 2019 के ऑपरेशन पराक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद शिव सिंह तथा शहीद गुरमेल सिंह एवं वर्ष 1976 के ऑपरेशन पराक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद रघुबीर सिंह के परिजनों को सम्मानित किया।

उन्होंने हेरिटेज पार्क के निर्माण में योगदान के लिए एलीन एप्लाइन्सिस के संयंत्र प्रमुख जे.एस. कांग तथा टोरेंट फार्मा बद्दी के संयंत्र प्रमुख सोमेन मेहती को भी सम्मानित किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल, दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, नालागढ़ के विधायक लखविन्द्र राणा अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं शहीदों के परिजन इस अवसर पर उपस्थित थे।

# केंद्र से कृषि विज्ञान केंद्र ऊना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का आग्रह:वीरेन्द्र कंवर

**शिमला/शैल।** भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की 93 वीं वार्षिक बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश से कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर व कृषि निदेशक नरेंद्र कुमार धीमान ने भाग लिया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री ने प्रदेश के कृषि सम्बंधित मुदों पर चर्चा करते हुए प्रदेश में पोटेटो सिस्ट निमेटोड की समस्या को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखते हुए कहा कि राज्य में आलू आय का मुख्य साधन है, तथा लगभग 15,100 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू का उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए लगभग 3 लाख क्विंटल बीज आलू के प्रमाणित बीज की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है। प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा आलू विकास केन्द्रों पर लगभग 55 हेक्टेयर क्षेत्र में फाउंडेशन बीज आलू का उत्पादन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षो से प्रदेश के आलू विकास केन्द्रों पर बीज आलू का उत्पादन कार्य पोटेटो सिस्ट निमेटोड के कारण प्रभावित हुआ है, जिससे प्रदेश के सरकारी फार्मो पर फाउंडेशन बीज आलू का उत्पादन संभव नहीं है, जिससे किसानों की आर्थिकी को बहुत नुकसान हो रहा है। इस समस्या बारे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा केंद्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान के माध्यम से सिस्ट निमेटोड के प्रबंधन हेतु विकसित तकनीक को प्रदेश सरकार और किसानों को हस्तांतरित किया जाए ताकि इस समस्या से निदान पाया जा सके। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर इस तकनीक को प्रयोग में लाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया की इस समय ऊना जिले में बड़े स्तर पर आलू का उत्पादन होता है, इसे मध्यनजर रखते हुए वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार से कृषि विज्ञान केंद्र ऊना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त दलहन व तिलहन फसलों पर आधारित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया, ताकि प्रदेश में दलहनों व तिलहनों की फसलों को बदावा दिया जा सके। कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने केंद्र सरकार का राज्य सरकार की ओर से राज्य में कृषि सम्बंधित कार्यक्रमों को बढावा देने के लिए समय-समय पर सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

# कन्दरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में चिन्हित:जय राम ठाकुर

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिला के कन्दरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के अगले फार्मास्यूटिकल हब के रूप में चिन्हित किया गया है और इस औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए अनेक फार्मास्यूटिकल व न्यूट्रास्यूटिकल इकाइयों ने अपनी रूची दिखाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्दरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है तथा यहां सड़क, रेल और हवाई सम्पर्क की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दे रही है।

उन्होंने कहा कि कन्दरौड़ी में न्यूट्रास्यूटिकल इकाई स्थापित करने के लिए मेफ्रो ऑरगेनिक लिमिटेड ने आज 100 करोड़ रुपये के निवेश सम्बन्धी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, जिसके माध्यम से 200 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व, कन्दरौड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 70 करोड़ रुपये के निवेश वाले ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकलज को स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जिससे 300 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इसे मिलाकर क्षेत्र में लगभग 170 करोड़ के निवेश और 500 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य और विशेषकर कांगड़ा क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर विशेष बल दे रही है। राज्य उद्योग विभाग को इन्वेस्टमेंट आऊटरीच प्रोग्राम के तहत क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास से न केवल क्षेत्र की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति ने राज्य सरकार की ओर से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

मेफ्रो ऑरगेनिक लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक अमित चड्डा ने कम्पनी की ओर से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।

डमटाल इन्डस्ट्री एसोसिएशन के महासचिव सुभाष महाजन ने कांगड़ा क्षेत्र को औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए स्थानीय उद्योगों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

# प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 389 इकाइयां स्वीकृत:बिक्रम सिंह

**शिमला/शैल।** उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1120.78 लाख रुपये लागत की 389 इकाइयां स्वीकृत की गई हैं, जिनके माध्यम से लगभग 3,064 युवाओं को रोज़गार के अवसर प्राप्त होगें। उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 237वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग की इकाइयों द्वारा करोड़ों रुपये के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन तथा विपणन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों को उनके घरद्वार के निकट रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि बोर्ड द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में 13 ऊन पिंजाई संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 2,428 भेड़ पालकों को 20,446 किलोग्राम ऊन पिंजाई, 7,880 किलोग्राम तेल पिराई व 436 वस्तुओं तथा 5,653 मीटर फिनिशिंग की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, कौशल विकास निगम, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं और बुनकरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को ऊन पिंजाई, तेल पिराई व फिनिशिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रदेश में ग्राम स्वरोज़गार की विचारधारा को मूर्त रूप प्रदान कर रहा है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि बोर्ड के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए अनुमानित 5.94 लाख रुपये प्रतिमाह व्यय किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को बोर्ड के सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए।

बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया, विशेष सचिव उद्योग सी.पी. वर्मा, अतिरिक्त नियंत्रक भण्डार किरन भंडाना, सीईओ एम.आर भारद्वाज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

# शराब के मूल्यों में बदलाव से अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगेगा और सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी

**शिमला/शैल।** राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को और अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। इसके लिये सभी आबकारी अनुज्ञापिओं से विचार विमर्श किया गया और नीतिगत सुझाव भी आमंत्रित किये गए। इसके अतिरिक्त, पड़ोसी राज्यों में शराब के मूल्यों एवं आबकारी नीति का भी अध्ययन किया गया। आबकारी अनुज्ञापिओं के सुझाव व अन्य राज्यों की आबकारी नीति का अध्ययन करने के पश्चात् इस वित्त वर्ष में शराब के मूल्यों में नीतिगत बदलाव किया गया है।

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अवैध शराब की बिक्री व तस्करी को रोकने के लिए शराब के मूल्य को तर्कसंगत बनाया गया है। देसी शराब के मूल्य में बदलाव करते हुए इसे तर्कसंगत और पड़ोसी राज्यों में बिकने वाली शराब के समकक्ष लाया गया, जिससे शराब की तस्करी पर रोक लगेगी। सभी आबकारी हितधारकों द्वारा इस नीति का स्वागत किया गया है। आबकारी नीति में बदलाव एवं शराब के मूल्यों में तर्कसंगत मूल्यांकन के फलस्वरूप प्रदेश में 95 प्रतिशत से अधिक शराब के कारोबार का आबंटन हो चुका है। इस नीति में सभी हितधारकों का ध्यान रखा गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि जहां जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में स्थित होटल एवं रेस्तरां के बार की फीस में कटौती की गई है, वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थित होटलों के बार की फीस को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। सरकार द्वारा शराब पर लगने वाले कोविड शुल्क को भी कम किया है। प्रदेश में शराब के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शराब के मूल्यों में किए गए बदलाव से प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगेगा और साथ ही सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। प्रदेश में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो, इसके लिए सरकार शराब के निर्माण से लेकर बिक्री तक के संचालन के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इस वर्ष लागू करने जा रही है। इसके लागू होने से शराब की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।

# जल शक्ति विभाग द्वारा प्रदेश की 1661 पंचायतों में मनाया गया विश्व जल दिवस

**शिमला/शैल।** राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के निदेशक जोगिंद्र सिंह चौहान ने बताया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग द्वारा प्रदेश की 1661 पंचायतों में विश्व जल दिवस मनाया गया।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं में पंचायतों व ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति की भागीदारी सुनिश्चित करने व उन्हें मजबूत करने के दृष्टिगत यह कार्यक्रम कार्यान्वयन सहायक ऐंजेंसियों के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर मनाया गया।

कार्यक्रम में जल गुणवत्ता, भू-जल संवर्द्धन, जल सरंक्षण, वर्षा जल संग्रहण, जल सदुपयोग जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। इस दिवस पर प्राकृतिक स्रोतों पर स्वच्छता अभियान, पानी की पाइपों की लिकेज को ठीक करने, जल जागरूकता रैली, नदी तटों की सफाई, जल जागरूकता रैली, स्कूली छात्रों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में पेंटिंग व नारा लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से अपने जल का स्वयं परीक्षण करने का प्रशिक्षण, पानी का संरक्षण, सदुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई।

# प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्धः जय राम ठाकुर

**शिमला/शैल।** हमारे समाज में महिलाओं की लगभग 50 प्रतिशत भागीदारी है और एक सशक्त और जीवंत समाज के निर्माण में महिलाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में हिमाचल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह मनस्वी को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने इस संक्रमण के प्रसार को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और 53 लाख मास्क तैयार कर निःशुल्क लोगों को वितरित किए गए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और यह सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित सभी योजनाओं का विवरण प्रदान करती हुई एक अलग जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी में यह मील पत्थर साबित होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना का उद्देश्य महिलाओं को निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत 3.25 लाख से अधिक निःशुल्क गैस कनैक्शन प्रदान किए गए हैं और हिमाचल देश का चूल्हा धुंआ मुक्त राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि शगुन योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के समय 31000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों को उनके सपने साकार करने में सहायता मिल रही है। योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को अब 35 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में काफी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सिलाई अध्यापिकाओं, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं, शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4600 रुपये, आशा कार्यकर्ताओं को 4700 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7850 रुपये, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को 3400 रुपये शिक्षा विभाग में कार्यरत जल वाहकों को 3800 रुपये प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से महिलाओं को राहत प्रदान हुई है।

मुख्यमंत्री ने आईटी प्रमुख वर्षा ठाकुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका तेजस्वनी का विमोचन भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीन तलाक प्रथा को समाप्त किया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने महिला अभ्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में सावित्री देवी फुले परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अगले वित्त वर्ष के बजट में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में आशातीत वृद्धि की है।

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ती रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार प्रदेश का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं कड़ी मेहनत से हर मुकाम हासिल कर सकती हैं। महिलाओं को समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में चार राज्यों में हुए चुनावों में भाजपा को पुनः सत्ता में लाने में महिलाओं की अहम भूमिका रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा की प्रत्येक पदाधिकारी प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सही परिप्रेक्ष्य में प्रभावी ढंग से प्रचार-प्रसार करें। महिला मोर्चा को महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नवोन्मेषी गतिविधियां भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकार योजनाओं के लाभार्थियों को संगठन से जोड़ा जाना चाहिए।

इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रशिम धर सूद ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने इस जानलेवा संक्रमण से बचाव के लिए सभी को निःशुल्क फेस मास्क प्रदान करना सुनिश्चित किया।

भाजपा महिला मोर्चा की शिमला जिला की अध्यक्ष अनिला ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर, प्रदेश बाल कल्याण परिषद की सचिव पायल वैद्य, प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव वंदना गुलेरिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

# दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए प्रदेश को 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्राप्तः सुरेश भारद्वाज

**शिमला/शैल।** शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में कुल दस राज्यों में निरन्तर तीसरी बार वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में भी हिमाचल प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि पुरस्कार स्वरूप भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है।

सुरेश भारद्वाज ने बताया कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी गरीबों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करके समूह के सदस्यों का क्षमतावर्द्धन करते हुए उनका सामाजिक तथा आर्थिक विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में प्रदेश में मिशन के अन्तर्गत 698 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए तथा 635 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2,447 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 508 एकल ऋण तथा 145 स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान किए गए। इस दौरान 39 आश्रय भवन संचालित किए गए।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में प्रदेश में मिशन के अन्तर्गत 420 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए तथा 757 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1,777 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 320 एकल ऋण तथा 149 स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि मिशन के अन्तर्गत दो वैंडर मार्किट का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा दो अतिरिक्त आश्रय भवन संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के गठन के तीन महीने के पश्चात 10 हजार रुपये रिवाल्विंग फंड दिया जा रहा है। लाभार्थियों को कौशल विकास घटक के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार घटक के अन्तर्गत कम ब्याज दरों पर आसान ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त शहरी आश्रय विहीन लोग जो खुले में सोते थे उनके लिए शहरी निकायों में आश्रय भवन संचालित किए जा रहे हैं। पथ विक्रेताओं के उत्थान के लिए उनका सर्वे करवा कर हर शहरी निकाय के लिए विक्रय योजना वेंडिंग प्लान बनाया जा रहा है। पथ विक्रेता अधिनियम के अन्तर्गत नगर विक्रय समिति का चुनाव भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी भारत सरकार की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा अथक परिश्रम किया जा रहा है तथा वित्त वर्ष 2021-22 में भी राज्य को दीनदयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त होगा।

# मुख्यमंत्री ने शिमला शहर में ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए 15 वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला शहर के ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत खरीदे गए 15 वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों से कचरे को निष्पादन क्षेत्र तक ले जाने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला को 34 वाहनों में से 15 वाहन प्राप्त हो गए हैं और शीघ्र ही शेष वाहन भी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कचरे के कुशल प्रबन्धन और ट्रैकिंग के लिए इन वाहनों में जीपीएस की सुविधा भी है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह वाहन 5.44 करोड़ रुपये की लागत से खरीदें गए हैं। इन वाहनों को नगर निगम शिमला के विभिन्न वार्डों में तैनात किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरा संग्रहण वाहनों में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग डिब्बों में एकत्रित किया जाएगा। प्रत्येक वाहन में एक अलग से संग्रहण टैंक भी लगाया गया है।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक सुरेन्द्र शौरी, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौण्डल, उप-महापौर शैलेन्द्र चौहान, पार्षदगण, नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली भी उपस्थित थे।

# राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइसिस पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में एनआईपीईआर के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने सोलन जिला के नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइसिस पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) मोहाली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम इस मेडिकल डिवाइसिस पार्क की अवधारणा, विकास और निष्पादन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी है। एनआईपीईआर मोहाली मेडिकल डिवाइसेस पार्क में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, जो उद्योग एवं शिक्षण गतिविधियों को जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उद्योग की स्थिरता के लिए इस तरह का जुड़ाव महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि प्रौद्योगिकी का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में किसी भी निर्माता के लिए निरंतर विकास और नवाचार को अपनाना एक अनिवार्यता है।

राज्य योजना विभाग ने इस पार्क को विकसित करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी को 74.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है और भारत सरकार का फार्मास्युटिकल विभाग भी शीघ्र ही इसके लिए 30 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता की पहली किस्त जारी करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसका राष्ट्रीय महत्व भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इसे स्टेट ऑफ आर्ट और क्षेत्र विशिष्ट पार्क के रूप में निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस पार्क में विनिर्माता उच्च मूल्य के उत्पादों का निर्माण करेंगे और इसके दृष्टिगत राज्य सरकार विश्व स्तर पर उद्योग-शोध क्षेत्र में जुड़ाव की सम्भावनायें तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग को भारत सहित इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जर्मनी जैसे देशों के निवेशकों के साथ इन्वेस्टमेंट आऊटरीच कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इन देशों में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि एक निवेश आऊटरीच का आयोजन पहले ही किया जा चुका है और इसके अन्तर्गत दक्षिण कोरिया का एक प्रतिनिधिमण्डल इसी मई माह में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आने वाला है।

निदेशक उद्योग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक राकेश कुमार प्रजापति ने इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), मोहाली के निदेशक प्रो. दुलाल पाण्डा ने संस्थान की ओर से हस्ताक्षर किए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

# क्या सरकार कर्ज लेकर घी पीने पर अमल कर रही है?

- 45 लाख की कैमरी खरीद से उठी चर्चा
- भ्रष्टाचार दबाने के लिए उसे उजागर करने वालों को ही डराने धमकाने पर आयी सरकार
- चार मंजिला मकान की खरीद चर्चा में

**शिमला/शैल।** प्रदेश के मुख्य सचिव के लिये 45 लाख की कैमरी गाड़ी खरीदे जाने को लेकर चर्चाओं का दौर चल निकला है। यह चर्चा इसलिए उठनी शुरू हुई है कि जिस वक्त इस गाड़ी की जानकारी सार्वजनिक हुई उसी वक्त जनता को रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और दवाइयां महंगी होने का तोहफा मिला। इससे पहले प्रदेश पर बढ़ते कर्ज तथा सरकार की फिजूल खर्ची की जानकारी कैग की रिपोर्टो के माध्यम से मिल चुकी है। कैग रिपोर्ट से यह खुलासा भी सामने आ चुका है कि 96 योजना पर इस सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है और न ही इसका कोई कारण बताया है। यही नहीं राजधानी शिमला में ही लक्कड़ बाजार बस स्टैंण्ड के पास कुछ दिन पहले कुछ दुकानें बनायी और अब उनको तोड़ दिया गया हैं। संजौली में महापौर के अपने वार्ड में कुछ दिन पहले एक रेन सैल्टर बनाया गया अब उसे वहां पर सीढ़ियां बनाने के लिये तोड़ दिया गया। सचिवालय में एनजीटी के आदेशों को नजरअंदाज करके निर्माण किया जा रहा था। एन जी टी के आदेश के खिलाफ सरकार प्रदेश उच्च न्यायालय में गयी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। अब या तो सरकार इस निर्माण को अदालती आदेशों की अवहेलना करके जारी रखें या उन अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करें जिनके कारण यह स्थिति खड़ी हुई है। शिमला का टाउन हॉल पिछले चार वर्षो से उचित उपयोग में लाये जाने के लिये तरस रहा है जबकि कर्ज के पैसे से इसकी रिपेयर हुई है। ऐसे कई मामले हैं जिनके सामने यह तस्वीर उभरती है कि सरकार सिर्फ कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है। अभी गाड़ी की खरीद की चर्चा शांत नहीं हो पायी है कि मुख्यमंत्री के आवास पर इको पार्क आदि बनाये जाने की खबरें बाहर आने लग गयी है।

सरकारी कर्मचारियों का हर वर्ग मांगे लेकर खड़ा हो चुका है। आउट सोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारियों को बार-बार यह भरोसा दिया जा रहा है कि सरकार उनके लिए स्थाई नीति बनाने जा रही है। यह व्यवहारिक सच्चाई कोई नहीं बता रहा है कि इन कर्मचारियों को लेकर सरकार कोई नीति बना ही नहीं सकती। क्योंकि यह लोग प्राइवेट कंपनियों/ठेकेदारों के नौकर हैं। सरकारी कर्मचारी बनने के लिये इन्हें पूरी सरकारी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिसमें आरक्षण, रोस्टर आदि सबकी अनुपालन सुनिश्चित करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कर्मचारियों के फ्रंट पर सरकार सुखद स्थिति में नहीं है। ऊपर से इस सबकी जिम्मेदारी पार्टी और सरकार का ही एक वर्ग पार्टी के ही दूसरे नेताओं पर डालने लग गया

है। इससे पार्टी के अन्दर भी गुटबाजी को अनचाहे ही उभार मिल गया हैं। कर्मचारियों की पैंशन की मांग पर जब सदन में मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि इसके लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने आग में घी का काम किया है। अब यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या कोई मुख्यमंत्री चुनावी वर्ष में अपने कर्मचारियों के प्रति इस तरह का स्टैंड ले सकता है। जब उपचुनाव में हार मिली थी तब उस हार के लिए महंगाई को जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। महंगाई तो अब फिर पहले से भी ज्यादा बढ़ गयी है और निकट भविष्य में इसके कम होने के आसार नहीं हैं

पार्टी के अंदर और बाहर इस वस्तुस्थिति पर नजर रखने वालों के सामने यह सवाल बड़ा होता जा रहा है कि क्या इस परिदृश्य में पार्टी पुनः सत्ता में वापसी कर पायेगी? क्या मुख्यमंत्री का राजनीतिक आकलन गड़बड़ा रहा है? क्या मुख्यमंत्री को उसके सलाहकारों और विश्वस्त अधिकारियों से सही राय नहीं मिल रही है? क्योंकि जब प्रशासन अपने भ्रष्टाचार और नालायकी को ढकने के लिये उसे उजागर करने वालों को ही डराने धमकाने का प्रयास करने लग जाये तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सलाहकार अब नेतृत्व को डूबो कर ही दम लेंगे। क्योंकि ऐसे सलाहकार ऐसे हालात में अपने भ्रष्टाचार की कमाई को निवेश करने में लगा देते हैं। एक सलाहकार का ऐसा ही एक निवेश चार मंजिला मकान की खरीद के रूप में विशेष चर्चा में चल रहा है। चर्चा है कि दो करोड के इस निवेश की रजिस्ट्री केवल पच्चास लाख में करवायी गयी है। कहते हैं कि जिस परिजन के नाम पर यह खरीद दिखाई गयी है उसकी आयकर रिटर्न से यह निवेश मेल नहीं खाता है। चर्चा है कि यह सब कुछ दिल्ली दरबार तक भी पहुंच चुका है।

# आय माननीयों की और आयकर जनता भरे को मिली उच्च न्यायालय में चुनौती

- विधायक महेंद्र सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, राकेश सिंह और होशियार सिंह भी बनाये गये प्रतिवादी
- आने वाले दिनों में 'एक विधायक एक पैंशन' के भी मुद्दा बनने की संभावना बढ़ी

**शिमला/शैल।** हिमाचल प्रदेश सरकार अपने विधायकों और मंत्रियों को मिलने वाले वेतन भत्तों के माध्यम से उनको हो रही आय पर दिये जाने वाले आयकर की अदायगी सरकारी कोष से करती है। आमदनी माननीयों की होती है और उस पर आयकर सरकार अदा करती है। जबकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जो उसके दायरे में आता है। फिर आयकर को लेकर कोई नियम कानून बनाना भी संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है राज्यों की विधानसभाओं के दायरे में नही आता है। संविधान में पूरी तरह परिभाषित है और बाकायदा इसकी अलग-अलग सूचियां बनी हुयी हैं कि केंद्र के दायरे में कौन से विषय आते हैं और राज्य कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। बल्कि कई ऐसे विषय भी हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय सांझी सूची में रखे जाते हैं और इनमें यदि कभी केंद्र और राज्य में विरोधाभास की स्थिति आ जाये तो उसमें राज्य की बजाये केंद्र के प्रावधान को अधिमान दिया जाता है। इस व्यवस्था में भी आयकर किसी भी गणित से राज्य के पाले में नहीं आता है। इसी वैधानिक स्थिति के कारण प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के इस आचरण को अदालत में चुनौती दी है। जिस पर उच्च न्यायालय ने जवाब तलब कर लिया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मनिकटाला और उनकी टीम के सदस्य यशपाल राणा, सुरेश कुमार, कपिल भारद्वाज तथा राकेश कुमार ने संविधान की धारा 226 के तहत याचिका दायर करके भाजपा विधायक महेंद्र सिंह कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री सीपीएम विधायक राकेश सिंघा निर्दलीय विधायक होशियार सिंह तथा विधानसभा को भी इसमें प्रतिवादी बनाया गया है। स्मरणीय है कि वर्ष 2017-18 से लेकर 19-20 तक सरकार ने माननीयों का 4,69,31,407 रुपए का आयकर अदा किया है। यह प्रावधान वर्ष 2000 में माननीयों के वेतन भत्तों और पैंशन से जुड़े अधिनियम 1971 में संशोधन करके किया गया तथा इस आशय की धारा 12 जोड़ी गयी। याचिकाकर्ताओं ने इसे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुये असंवैधानिक करार देकर निरस्त करने की मांग की है। यह याचिका उस समय आयी है जब प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पैंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। राष्ट्रीय स्तर पर माननीयों की पैंशन मिलने के विरोध की याचिका सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची हुई है।

उधर माननीयों ने हर टर्म में जीतने पर अतिरिक्त पैंशन मिलने तक का प्रावधान कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने 'एक विधायक एक पैंशन' के सिद्धांत की वकालत करते हुये पंजाब में इसे लागू करने की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में यह तय है कि आने वाले दिनों में यह एक बड़ा और राष्ट्रीय मुद्दा बन जायेगा। इस परिपेक्ष में यह देखना रोचक होगा की आयकर वाले मामले में सरकार और प्रतिवादी बनाये गये विधायक क्या जवाब देते हैं। क्योंकि पार्टी बनाये गये सभी विधायकों को अपना-अपना जवाब दायर करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका एक प्रभाव पड़ना तय है। क्योंकि बहुत संभव है कि हिमाचल की तरह अन्य भी कई राज्यों ने ऐसा प्रावधान कर रखा हो। यह भी तय है कि इसके बाद प्रदेश में 'एक विधायक एक पेंशन' पर भी आवाजें उठना शुरू हो जायेंगी जो चुनाव आते-आते एक बड़ा मुद्दा बन जायेगा।

# क्यों नहीं आ पाया

.....पृष्ठ 1 का शेष

कांग्रेस भाजपा के ही वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार उन्ही की आत्मकथा में केंद्र की भाजपा सरकारों के खिलाफ लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों पर जुबान नहीं खोल पाये हैं। जबकि इन आरोपों के माध्यम से भाजपा को शिमला से लेकर दिल्ली तक घेरा जा सकता था। इससे यह सवाल उठने लग पडा है कि प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व भाजपा से डरकर चल रहा है या इसका कोई और बड़ा कारण है। आज प्रदेश की राजनीति जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो गयी है वहां यदि कांग्रेस इस स्थिति से बाहर नहीं निकलती है तो उसका भविष्य प्रश्नित ही रहेगा। इस समय कांग्रेस को प्रदेश हित में इस दुविधा की स्थिति से बाहर निकलने के लिये नया नेतृत्व तलाशना आवश्यक हो जायेगा।